an>

Title: Need to give constitutional status to National Commission for Backward Classes.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, देश में सबसे बड़ी तादात में, देश के पिछड़ों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आज से नहीं सन् 1931 की जनगणना, जनगणना के बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट, रिपोर्ट के बाद इंदिरा साहनी केस और तमाम संघर्षों के बाद विशेषकर समाजवादियों के संघर्ष के बाद, आदरणीय नेता जी और उनके तमाम साथियों के संघर्षों के बाद देश के अंदर 27 फीसदी लोगों को आरक्षण मिलने का काम हुआ। एक नहीं अनेक मुद्दों पर पिछड़ों के साथ अन्याय है। अगर आरक्षण मिला तो उससे पहले क्रीमी लेयर के माध्यम से उनको रोकने का पूरा षडयंत्र किया गया। ये आ न पाएं किसी तरह, पढ़ न जाएं, इसलिए क्रीमी लेयर की ऐसी सीमा लगा दो कि ये आय ही नहीं पाएंगे। इसके बाद अभी सदन में जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई। जातिगत जनगणना के बारे में पूरा सदन एक था, लेकिन मैं उस समय की यूपीए सरकार को दोष दूंगा कि यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं होने दी। सभापति महोदय, चाहे यूपीए हो, या एनडीए हो या और भी लोग रहे हों, पिछड़ों के साथ भेदभाव और अन्याय लगातार हुआ है। अभी मेरे पास आंकड़े हैं। अगर आप पढ़ने की अनुमति देंगे तो देश के अधिकांश विभागों में पिछड़े वर्ग की तादाद अगर ग्रुप ए की बात करेंगे तो कहीं भी तीन चार फीसदी से ऊपर किसी विभाग में नहीं है। बहुत सारे विभाग हैं, जहां जीरो फीसदी हैं। कल ही एचआरडी मिनिस्टर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि देश के अंदर प्रोफेसरों की स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालय में आठ फीसदी है। यह इसलिए है कि इस समिति की सिफारिश, मंडल आयोग और तमाम जो चीजें हैं, उन चीजों की निगरानी की जो जिम्मेदारी है, वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ऊपर है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके पास कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। कल एचआरडी मंत्री ने इस सदन में कहा कि मैंने कुलपतियों को कई बार एडवाइज़री भेजी, कुलपतियों को कई बार लिखा, लेकिन कुलपति नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ कीजिए या मत कीजिए, देश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, सबको सही करने का इंतजाम, व्यवस्था को सही करने का इंतजाम देश का पिछड़ा वर्ग आयोग कर देगा। लेकिन जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे, तब तक पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। चाहे कितनी ही बातें कर लो कि मोदी जी बैकवर्ड हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि बैकवर्ड लोगों की रक्षा सम्मान और उनके हकों की रक्षा एनडीए की सरकार भी नहीं कर रही है। यूपीए की सरकार ने तो उपेक्षा की ही थी, एनडीए की सरकार भी साथ नहीं दे रही है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:

Shri Laxmi Narayan Yadav,

Dr. Manoj Rajoria,

Shri Jai Prakash Narayan Yadav,

Dr. A. Sampath,

Shri Ganesh Singh and

Shri Jitendra Chaudhury are permitted to associate with the issue raised by Shri Dharmendra Yadav.